

भाग एक : खण्ड पन्निह

मध्य प्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987

(बर्मांक 32, सन् 1987)

(दिनांक 31 जुलाई 1987 को राष्ट्रपित की अनुमित ूाप त हुई, अनुमित "मध्य प्रदेश राजपऽ (असाधारण) में दिनांक 12 अगः त 1987 को ूथम बार ूकाशित की गई")

सरकार द्वारा बेताओं को दीघर्का िलक अविध के िलये बेची गई या ूदाय की गई वन उपज के िलए उचित कीमत ूाप त करने हेतु, कितपय करारों की समय-समय पर पुनरीक्षित करने की शिक्त ूाप त करने और आय की हांिन को रोकन तथा पुनरीक्षित करारों को ूवृत् त करने और कितपय अन् य िवषयों के िलये उपबन् ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज् य के अड़तीसवें वषर् में मध्य ूअधिनियमित हो -

देश िवधान मंडल द्वारा िनम् निलिखत रूप में यह

धारा 1. संक्षिप् त नाम, िवः तार और ूारम् भ - (1) इस अधिनियम का संक्षिप् त नाम म.०. वन उपज के करारों का पुनरीक्षण अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका िवः तार सम् पूणर् मध्य ूदेश राज् य पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को ूवृत् त होगा िजसे राज् य सरकार, अधिसूचना द्वारा िनयत करे।

िटप् पणी

म. ०. शासन ने अपनी अधिसूचना बर्मांक 1301-दस 3-88 दिनांक 2 मई, 1988 द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 से इस अधिनियम को ूभावशील घोषित िकया है। उक् त अधिसूचना म.०. राजपऽ (असाधारण) दिनांक 2/5/88 को पृष्ठ 873 पर ूकाशित हुई।

धारा 2. पिरभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक िक संदर्भ से अन् यथा अपेक्षित न हो -

(क) "करार" के अन् तर्गत आयेगी कोई संविदा, अनुज्ञिप्त बंधपऽ, िवलेख या अन् य दः तावेज, िजसके द्वारा राज् य सरकार, ऐसी दः तावेज में िविनिदर् ट िनबन् धनों तथा शतोर् पर, िकसी दीघर्का िलक अविध के िलये, ूतिफलाथर्, िकसी वन उपज का िकसी व् यिक्त को िवबय या ूदाय करने का अथवा कोई वन उपज िकसी व् यिक्त द्वारा संमहीत िकये जाने और हटाये जाने की अनुज्ञा देने के िलए करार करती है।

(ख) "वन उपज" का वही अथर् होगा जो उसे म.०. राज् य को यथा लागू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) में िदिया गया है;

(ग)

"दीघर्का िलक अविध" से अभूेत है बारह मास के अधिक की कोई कालाविध; (घ) "बेता" से अभूेत है, िकसी कम् पनी या संगम या व् यिष्ट िनकाय को, चाहे वह िनगिमत हो या न हो, सिम्मिलत करते हुए कोई ऐसा व् यिक्त जो िकसी करार के अधीन राज् य सरकार से कोई वन उपज बय करता है या िजसे राज् य सरकार द्वारा िकसी वन उपज का ूदाय िकया जाता है या जो राज् य सरकार से कोई वन उपज अभूाप त करता है।"

1.

यह अधि. म.०. राजपऽ असाधारण, दिनांक 12.8.87 के पृष्ठ 1599-1601 पर ूकाशित हुआ।

धारा 3. वन उपज के िवबय या ूदाय के करारों का पुनरीक्षण करने की राज् य सरकार की शिक्त - तत् समय ूवृत् त िकसी िविध में तथा इस अधिनियम के ूारम् भ होने की तारीख को िवद्यमान िकसी करार में या िकसी ऐसे करार में जो राज् य सरकार द्वारा िकसी बेता के साथ इस अधिनियम के ूारम् भ होने की तारीख को या उसके पँ चात् िकया जाये, अन् तिवर् ट िकसी बात के होते हुए भी, राज् य सरकार के िलए यह िविधपूणर् होगा िक वह िकसी ऐसे करार के िनबर्थों तथा शतोर् में से िकसी भी िनबन् धनों तथा शतर् में समय-समय पर, राजपऽ में ूकाशित आदेश द्वारा, िनम् निलिखत ूयोजनों में, िकसी भी एक या अधिक ूयोजनों के िलये, पिरवधर्न करे या उसे ूितः थापित करे, हटा दे या उसे अन् यथा संशोधित करे, अथार्त् -

(क) बेता को वन उपज के िवबय या ूदाय के िलये कीमत या दर के पुनरीक्षण या िनयतकालिक पुनरीक्षण के िलये उस दशा में उपबन् ध करना, जबिक ऐसे करार में यथािःथित ऐसे पुनरीक्षण या िनयतकालिक पुनरीक्षण के िलये कोई उपबन् ध न हों। और जहाँ ऐसे करार में ऐसी िनयतकालिक पुनरीक्षण के िलये कोई उपबन् ध हों, वहा पुनरीक्षण की कालाविध में कमी या वृद्धि करने हेतु उपबन् ध करना परन् तु एक बार िनयत की गई कीमत या दर उस तारीख से, िजसको िक ऐसी कीमत या दर ूवृत् त हुई को कम से कम बारह मास की कालाविध तक राज् य सरकार द्वारा पुनरीक्षित नहीं की जा सकेगी;

(ख) उस कीमत या दर के, िजस पर वन उपज का िवबय या ूदाय बेता को िकया जाना है, पुनरीक्षण के समय, वृद्धि की उस अधिकतम सीमा को, जो ऐसे िकसी करार में अधरोपित की गई है, हटाने या उसे उपातिरत करने का उपबन् ध करना;

(ग) उसे तौल माप की इकाई में, िजसमें उस उपज की तौल, मापन या गणना बेता या ूदाय के ू योजन के

लिए या उस वन उपज के लिये कीमत का दर ठाकरित करने या वसूल करने के योजनों के लिये उपबन्ध करना, किन्तु वह इस कारण कि जिससे उस वन उपज के, जिसका विषय या दूदाय बेता को करने का करार किया गया है, परिणाम में तात्विक या सारवान् परिवर्तन न हो; (घ) उस वन उपज के परिमाण को, जिसका कि करार के अधीन विषय या दूदाय बेता को किया जाने का करार किया गया है, जलागम क्षेत्रों (केचमेन्ट एरियाज) का समुचित पुनर्समायोजन करके, उपातिरत या पुनः आवंटित करना।

धारा 4. बेताओं की बेची या दूदाय की गई वन उपज की कीमत बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी -

- (1) वन उपज के विषय या दूदाय के लिये, धारा 3 द्वारा नियत कीमत या दर में किसी पुनरीक्षण के समय नियत की जाने वाली कीमत या दर, ऐसे पुनरीक्षण के समय होने वाले ऐसे वन उपज के उस बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित रीति में अवधारित किया जाए।
- (2) जहाँ कीमत या दर पुनरीक्षण के समय एक बार में बारह मास से अधिक की किसी कालाविध के लिये नियत की जाती है, वहाँ राज्य सरकार, उस कालाविध के दौरान, जिसमें कि पुनरीक्षित कीमत या दर वृत्त रहनी है, उस वन उपज के बाजार मूल्य में होने वाली पूर्वानुमानित वृद्धि के लिये कीमत या दर में वार्षिक वृद्धि के लिये उपबन्ध कर सकेगी।

धारा 5. निबन्धनों तथा शर्तों के भंग के कारण करारों का पर्यवसान करने की राज्य सरकार की शक्ति -

- (1) तत् समय वृत्त किसी विधि में तथा इस अधिनियम के धारम्भ होने पर या उसके पचात् की गई, अन्तिवर्त किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार बेता द्वारा करार में समय-समय पर यथा-संशोधित निबन्धनों तथा शर्तों में से किसी भी निबन्धन तथा शर्त को भंग किये जाने के कारण ऐसे करार का, बेता को इस बाबत हेतु दिशर्त करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पचात् कि उस करार का क् यों न पर्यवसान कर दिया जाए और ऐसे पर्यवसान के लिए उसे एक मास की सूचना देने के पचात् किसी भी समय पर्यवसान कर सकेगी।
- (2) ऐसे मामलों में राज्य सरकार का विनिर्णय अन्तिम होगा।

धारा-5 ब. करारों तथा संविदा की समाप्ति - तत् समय वृत्त किसी विधि में तथा म.प्र. व.उ. करारों का (संशोधन) अधि. 1996 के वृत्त होने की तारीख को विद्यमान, किन्तु हीं करारों में या किसी ऐसे करार में, जो राज्य सरकार द्वारा किसी बेता के साथ ऐसे अधि. के धारम्भ होने पर या उसके पचात् किया जावे अन्तिवर्त किसी बात के होते हुए भी वृक्ष, लकड़ी, कांठ या अन्य वन उपज के दूदाय के लिये राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई करार या मंजूर किया गया कोई पट्टा या दः तावेज इस अधिनियम के धारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान होने पर वृत्त नही रहेगा।

(2) ऐसे मामलों में राज्य सरकार का विनिर्णय अन्तिम होगा।

(3) उपरोक्त (1) के अधीन करारों की समाप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या विधिकार्यविहयां किसी न्यायालय या अधिकरण में नहीं होगी।

धारा 6. बेता एक मास की सूचना देने के पचात् करार का पर्यवसान कर सकेगा - यदि, धारा 3 के अधीन किसी करार के निबन्धनों और शर्तों में किया गया कोई संशोधन या उस धार के अधीन वन उपज के विषय या दूदाय के लिये कीमत या दर में किया गया कोई पुनरीक्षण, बेता को त्रितमाह्य न हो तो वह अपने विकल्प पर, उस तारीख से, जिसको कि यथास्थित निबन्धनों और शर्तों में किया गया संशोधन अथवा कीमत या दर में किया गया पुनरीक्षण उसे संसूचित किया जाता है, छह मास की कालाविध के भीतर, राज्य सरकार के एक मास की लिखित सूचना देकर, उस करार का पर्यवसान कर सकेगा और तदनुसार वह करार सूचना की कालाविध के खत्म होने पर पर्यवसित हो जाएगा।

धारा 7. नियम बनाने की शक्ति -

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के योजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्वाकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बना सकेगी।

(2) विशिष्ट तथा और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर त्रितकूल ठाभार डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समः त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये बनाये जा सकेंगे, अर्थात् - (क)

धारा 3 के अधीन करार में किए जाने वाला ठाः तावित संशोधन की या कीमत या दर में किये जाने के लिये ठाः तावित किसी पुनरीक्षण की सूचना देने के लिए और ठाः ताव के विरुद्ध हेतु दिशर्त करने के लिए बेता को अवसर देने के लिए,

(ख) वे सिद्धांत जिन पर, वह रीति जिसमें और वह ठाधिकारी जिसके द्वारा धारा 4 के योजनों के लिए बाजार मूल्य अवधारित किया जायेगा।

(ग) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जो विहित किया जाये।

(3)

इस अधिनियम के अधीन बनाये समः त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

____ 1. धारा 5 क म.ू. वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (संशोधन) अधिनियम 1996 (ब. 19 वर्ष 1996) द्वारा अन्तः
थापित। म.ू. राजपS (असा.) दिनांक 6-12-96 का पृष्ठ 1061-1062 पर ूकाशित।

